श्री देबेन सेन : क्या यह सही है कि एल० आई० सी० की मुख्य मांग यह है कि आटोमेशन और इलेक्ट्रिक काम्प्यूटर्ज को चालू न किया जाये, क्योंकि उन मे कर्मचारियों के सरप्लस हो जाने का खतरा हैं; यदि हां, तो उस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह एक मांग है। ऐसी तो अनेक मांगें हैं। लेकिन इस मांग को मैं कभी कुबूल करने के लिए राजी नहीं हूं।

गैस, एक सस्ता ईंधन

+

*1508. **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री शिव चरण लाल :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोल के परिष्करण के समय प्राप्त होने वाली गैस को तरल ईंधन में परिवर्तित किया जाता है तथा अपेक्षाकृत सस्ते ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1970-71 तक इस प्रकार की गैस का उत्पादन करने की हमारी क्षमता 2 लाख टन हो जायेगी किन्तु इस समय हम ऐसे केवल 2000 टन ईंधन का उत्पादन करते हैं तथा शेष क्षमता की उसे जला कर नष्ट कर देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir, A portion of the refinery Gases, consisting of propane and butane can be liquified under pressure and used as fuel under the name of liquified petroleum gas. The other gaseous portions including Methane, the main constituent, cannot be so liquified and are either burnt in the Refinery boilers or flared off.

(b) During 1967, the total production of L. P. G. was 75,239 tonnes. The production was limited mainly by the scarcity of steel cylinders, and the gases not so liquified as a result, were used as fuel in the refinery boilers. By 1971 the demand for L. P. G. is expected to be 155,000 tonnes and this will be met through increased indigenous production.

(c) Does not arise.

श्री महाराज सिंह भारती : शहरों की बढ़ती हुई आबादी और उसमें मालदारों की बढ़ती हुई आबादी के कारण गैस की बड़ी भारी मांग चल रही है। मंत्री जी ने फ़रमाया है कि यह मांग बढ़ कर 1,55,000 टन हो जाने की आशा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान के हर बड़े शहर में गैस की एजेन्सी लेने के लिये, और खरीदने के लिए भी, हजारों लोग तैयार हैं ? मंत्री महोदय ने जो मांग बताई है, क्या वह असली मांग से बहुत थोड़ी नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : इसके बारे में इंडियन पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने मार्केट सरवे कर के जो फ़िगर्ज़ बताए हैं, मिनिस्टर साहब ने उन्हीं के बेसिस पर जवाब दिया है।

श्री महाराज सिंह भारती : मंत्री जी का जवाब भी ठीक है और सरवे वालों की फ़िगर्ज़ भी ठीक हैं। वे लोग पचास, साठ घरों में चले गये होंगे, जो गैस मांगने वाले नहीं होंगे। आज स्थिति यह है कि हिन्दुस्तान के हर शहर में गैस की एजेन्सी मांगने वालों की लाइन लगी है और लोग उसको खरीदना चाहते हैं। मंत्री महोदय ने फ़रमाया कि इस गैस को लिक्विफ़ाइड करने में बड़ी दिक्कत सिलेन्डरों की है क्या यह सच नहीं है कि गैस के लिए जरूरी सिलेन्डर देश में उपलब्ध हैं और देश में बन सकते हैं; यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो उन को क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : They are manufacturing a few cylinders. The Allwyns are doing for IOC and other companies are doing for Burmah Shell and Caltex. The main bottleneck is the special steel that is required and the more indigenous steel is produced on these lines the more quickly we will be able to achieve self-sufficiency in indigenous production of the cylinders.

श्री महाराज सिंह भारती : क्या स्टील को इम्पोर्ट नहीं कर सकते ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : We are importing some steel for the time being.

SHRI MANUBHAI PATEL : Is it only shortage of cylinders or is there some defect with the distributing channel of the IOC also ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : I am not aware of any such defects. It is mainly paucity of steel.

श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भारतवर्ष में ईंधन का अभाव होता चला जा रहा है और उसके अभाव में गोबर को खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जब कि वह खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकता है ? क्या सरकार इस गैस का अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने की ओर ध्यान देने का विचार रखती है, ताकि भारतवर्ष के मूल्यवान खाद की रक्षा हो सके ?

श्री अशोक मेहता : जी हां । जहां तक इस गैस के सिलेन्डरों का सम्बन्ध है, एक लाख सिलेन्डरों के लिए आर्डर दिए गये हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे सिलेन्डर जल्दी आयेंगे ।

SHRI M. B. RANA : I come from a district where for the last several years natural gas is being burnt. May I know whether Government has any scheme to control that gas and make use of it for business purposes ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : Some of it, as I have already explained, which cannot be liquified has to beflased off. With regard to the part which can be liquified every effort is made to bottle it and use it.

श्री नाथूराम अहिरवार : आज देश में ईंधन की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है और लोग गोबर का प्रयोग ईंधन के काम के लिये करते हैं । किसान चाहते हैं कि वे गोबर के गैस प्लांट बनायें, लेकिन उनके पास इसके लिए साधन नहीं हैं । क्या सरकार उनको आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है, ताकि वे लोग गोबर के गैस प्लांट बना कर ईंधन का काम चला सकें और जो गोबर बचे, उसकी खाद तैयार की जा सके ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : I may very humbly submit that this Ministry is not concerned with that gas.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : Has the Government attempted an economic analysis of the total quantity of gas that will be available for liquification in all the refineries and the quantum of cylinders that would be required to contain it including the natural gas that would be available so that this valuable source of gas is not frittered away for mere lack of steel.

SHRI RAGHU RAMAIAH : It is a result of that very careful assessment that I have given the figures in answer to part (b) of the question. As regards cylinders every effort is being made to make the country selfsufficient in production.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : I was talking about economic assessment. I want to know whether such an assessment has been made to know whether it would be far more economical to import steel for making cylinders rather than fritter away the gas that is available ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : The answer is obvious. It is a selfevident proposition. You need the steel to bottle it. You do not have it. So you have to import steel.

श्री राम धन : क्या यह सच है कि दिल्ली नगर में गैस की कीमत 21-78 रुपये प्रति-सिलेंडर से बढ़ा कर 21-95 रुपये कर दी गई है; यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : Gas is sold at different prices by different companies. So far as Delhi is concerned Burmah Shell, I understand, is selling 14.5 kilograms at Rs 21.91, ESSO is selling 12.8 kilograms at Rs. 19.34, and IOC is selling 15 kilograms at Rs. 21.78, depending on the cost of production, agency dealership terms and various other factors.

SHRI SAMAR GUHA : About gas combinations there are the somewhat lower aliphatic and aromatic type of compounds also. Propane and butane are of the higher types The lower types can very easily be absorbed by water and they can be converted into alcohol. May I know whether methane and benzine can be thus utilised and used for chemical purposes and, if so, may I know why Government is not making a survey for the utilisation of these lower fraction of compounds ? Secondly, Minister has stated that the difficulty is in preparing cylinders and that too of a particular type of steel. Have the Government enquired about the possibility of manufacturing that special type of steel for the preparation of cylinders; if so, may I know when that type of steel in in adequate quantity can be produced in the country ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : A part of it is already being manufactured in the country. It is difficult to say when the whole quantity will be manufactured. As regards chemical analysis of other fractions, I am sure effort is made to find out the most economic use of them. In any case, it is a valuable suggestion and will be certainly considered.

SHRI SHEO NARAIN : If the Government cannot solve the problem in the public sector, why do they not hand it over to the private sector ?

MR. SPEAKER : Even if they want to hand it over, will they say it now ?

SHRI PILOO MODY : Let them confess it, one way or the other.

पिछड़े वर्ग क्षेत्र में लद्दाख का शामिल किया जाना

1509. श्री कुशोक बाकुला : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में लद्दाख देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लद्दाख को पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए सरकार से बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी लद्दाख को पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्र में शामिल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या लद्दाख को अब पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में शामिल करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) यह मत का विषय है। पहले भी देश के अनेक भागों से इस प्रकार के दावे किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। उसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 244 (i) तथा 242(i) जम्मू तथा कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। "पिछड़े वर्ग क्षेत्र" पद की सार्थकता समझ में नहीं आती है।

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : The question itself asks for the opinion of the Government and the answer is that it is a matter of opinion.

SHRI RANGA : Some clerk has written the answer and the Minister has read it.

श्री कुशोक बाकुला : लद्दाख शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में देश के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र को पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिये मैं आपसे बार-बार निवेदन करता रहा हूं। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि लद्दाख की हालत को देख कर इस को किसी भी सूरत में शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के वर्ग में शामिल किया जाय ?

DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA: I have already explained that according to the Constitution Ladakh cannot be declar-